Lifting ban on prosecution of public servants without prior clearance

*135. SHRI GOVINDRAM MIRI;
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to lift the ban on prosecution of public servants without prior clearance/approval of Government/President/Governors/Heads of the Department etc.

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) Requirement of previous sanction of the Central Government State Government or the Head of the Department concerned, to prosecute a public servant in a Court of Law for certain offences is provided under Section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988. Since this requirement has been provided under the law of the land, the same cannot be termed as ban on prosecution of public servants and, consequently, the Question of lifting of any such ban does not arise.

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

*136. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और क्या वांछित परिणाम प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त राज्य के सभी गांवों को कब तक विद्युतीकरण किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3210 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4752 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्य में शेष गांवों को नौवीं योजना तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत आपूर्ति स्थिति, संचारण तथा वितरण प्रणाली का कुल नेटवर्क जिसे स्थापित किया जा सकता है तथा अन्य संगत निवेशों पर निर्भर करते हुए विद्युतीकरण किया जाएगा।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

*137. **श्री अजीत जोगी:**
श्री वी॰ हनुमंत राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अन्तरिक्ष कार्यक्रम हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या करण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए कुल 3925.66 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध की गई थी। अन्तरिक्ष विभाग के लिए बजट अनुमान 1997-98 में 1171.10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Permanent Seat in U.N. Security Council

*138. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether he began a high pitched campaign to garner support for India's